(b) whether it is also a fact that every year the power units go on adding their capacity in 100 to 1500 M.W on 1st April, which were really not achieved;

(c) whether the above is true to most of the major thermal power plants; and

(d) if so, whether Government would check this practice and make it more actual and real?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ENERGY ((SHRI VIKRAM MAHAJAN): (a) No. Sir.

(b) to (d). In any power generation unit, after the physical works are completed, the unit takes quite sometime to stabilise. When a thermal unit is commissioned, it runs for a few days and then the same is stopped for examination of the bearings etc. to check various components as prescribed for proper commissioning of the unit. The gap between rolling (a prestage for synchronisation) varies from a few weeks to a few months depending upon the teething troubles of the unit concerned.

"शोध" चलचित्र

2997. प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस आलोचना की जानकारी है कि "शोध" चलचित्र भारतीय जनता के मस्तिष्क पर देश की गरीबी के बारे में अतिशयोक्तिपूर्ण छाप छोड़ता है;

(ख) क्या यह सच नहीं है कि इस तरह के चलचित्र विदेशों में भारत की गरीबी के बारे में गलत भ्रांति पैदा करते हैं;

(ग) क्या यह भी सच नहीं है कि इस चलचित्र में दिखाई गई गरीबी देश के किसी भी भाग में नहीं है; और

(घ) क्या सरकार का विचार ऐसे चलचित्रों पर प्रतिबन्ध लगाने का है जो दर्शकों के दिमाग में भ्रान्ति पैदा करते हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (कुमारी कुमुदबेन एम० जोशी): (क) से (घ). सभी फिल्में चलचित्र अधिनियम, 1952 और इस के अन्तर्गत जारी मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार फिल्म सेन्सर बोर्ड द्वारा सेन्सर की जाती हैं। अधिनियम की धारा 5(ख) में निर्दिष्ट बातों, जो संविधान के अनुच्छेद 19(2) पर आधारित है, के आधार पर ही किसी फिल्म पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है या उस में कांटछांट करने का आदेश दिया जा सकता है। फिल्म सेंसर बोर्ड फिल्म की जांच भारत में प्रदर्शन के लिए उस की उपयुक्तता को ध्यान में रख कर करता है और उसको निर्बन्धित या अनिर्बन्धित दर्शकों के लिए प्रमाणीकृत करत है। बोर्ड इस बात का ध्यान रखता है कि ऐसी कोई चीज पास न हो जो मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार आपत्तिजनक हो। तथापि, फिल्में संवेदनशील सामग्री है और उन का प्रभाव एक व्यक्ति, से दूसरे व्यक्ति पर भिन्न भिन्न होता है जो उनकी शिक्षा, मनोवृत्ति वातावरण, आदि पर निर्भर करता है। इसलिए यह प्रश्न कि फिल्म "शोध" में गरीबी का बढ़ा-चढ़ा कर चित्रण किया गया है या नहीं, एक ऐसा मामला है जिस पर अपने अपने मत हों सकते हैं। यह उल्लेखनीय है कि फिल्म "शोध" को 24 वें राष्ट्रीय पुरस्कार समारोह में "सर्वोत्तम फीचर फिल्म के लिए पुरस्कार" दिया गया है।